

CM Chhattisgarh releases RGGBKMNY installment & launches online Monitoring Portal of Revenue Department

The Chief Minister of Chhattisgarh Shri Bhupesh Baghel on 31st March 2021, transferred a total amount of Rs. 71.8 Crore to the beneficiaries of RAJIV GANDI GRAMIN BHOOMIHIN KRISHI MAJDOOR NYAY YOJNA, in order to provide financial support and justice to 3.55 lakh Rural Landless Families.

The portal <https://rggbkmny.cg.nic.in> has been developed by NIC, Chhattisgarh. It is a portal unique of its kind involving Beneficiaries filing forms and got verified by Patwaris and submitted to Secretaries of Panchayat. The data entry has been done at Janpad level and transferred online to Tehsildars for verification. After verification of Tehsildars, Gram Sabha approvals had been taken and a final list was prepared and finally the payments has been done via DBT with the help of ICICI bank.

Hon'ble CM also inaugurated one online Monitoring Portal of Revenue under (<https://revenue.cg.nic.in>) wherein Time Limit barring cases are identified and the proper cause for non-compliance is entered by the officers.

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

स्वेतिहर मजदूरों को प्रति परिवार ₹6000 सालाना

10 लाख से अधिक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक लाभ



पंजीयन विवरण

पंजीयन क्रमांक के द्वारा

☐ नाम के अंत से

☐ मोबाइल नंबर के आधार पर



पंजीयन विवरण

पंजीयन कं. XXXXXXXXX

रिजिस्ट्री का नाम राम

माता / पिता / पति का नाम सीताराम

मोबाइल नंबर XXXXXX2489

चित्रा अशोक

प्राप्त सिद्धि

First Installment

Payment Status Paid

Account No. XXXXXXX5222

Date 21/01/2022 00:00:00

Amount 2000

Payment Reference No. XXXXXXXXXX

वापस जायें



राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (<https://rggbkmny.cg.nic.in>)

- छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से "राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनके शुद्ध आय में वृद्धि करना है।
- योजनान्तर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के उन मूल निवासियों को होगी जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।
- राज्य में योजनान्तर्गत 3,55,402 पात्र परिवार है। योजना के शुभारंभ अवसर पर दिनांक 03.02.2022 को पात्र हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि प्रदाय की गयी।

- इस कड़ी में पात्र हितग्राहियों को दिनांक 31.03.2022 को 2000/- रूपए की द्वितीय किश्त प्रदाय किया जा रहा है। पात्र परिवारों को कुल राशि 71 करोड़ रूपए का अंतरण DBT के माध्यम से किया जा रहा है।

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन चिन्हित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रतिवर्ष राशि 6000/- रूपए से बढ़ा कर 7000/- रूपए प्रदाय करने की घोषणा की गयी है।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के समीक्षा हेतु Online monitoring पोर्टल (<https://revenue.cg.nic.in> & <https://bhuiyan.cg.nic.in>)

राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर किया जाना है। परंतु राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम नागरिकों की सुविधा एवं राजस्व प्रकरणों की सतत समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था किए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए थे। नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भुइयां सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिए मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय राजस्व मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिव राजस्व विभाग, संचालक भू-अभिलेख, संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर के स्तर से सीधे मॉनिटरिंग किया जाएगा।

04 नवीन अनुविभाग एवं 23 नवीन तहसील

वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल अनुविभागों की संख्या 96 है तथा कुल तहसीलों की संख्या 179 है। नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी।

4 नवीन अनुविभागों का गठन -

4 नवीन अनुविभाग - तोकापाल, मरवाही, भैयाथान, मैनपुर का गठन दिनांक 31/03/2022 को किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रदेश में अब • कुल 100 अनुविभाग होंगे।

• 23 नवीन तहसीलों का गठन -

23 नवीन तहसील - सीपत, बोदरी, सकोला (कोटमी), अड़भार, सरिया, छाल, बरपाली, अजगरबहार, पसान, चांदो, रघुनाथनगर, डोरा-कोचली, बिहारपुर, सुहेला, भटगांव, अहिवारा, नांदघाट, सरोना, बारसूर, कुटरू, गंगालूर, छोटेडोंगर, कोहकामेटा का गठन दिनांक 31/03/2022 को किया गया।

इस प्रकार से प्रदेश में कुल 202 तहसील होंगे।

राजस्व प्रकरणों की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग

व्यवस्था

■ मुख्यमंत्री ने किया
पोर्टल लांच

■ सीएम कार्यालय
से भी निगरानी

■ नवभारत ब्यूरो। रायपुर
www.navbharat.news

राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय से राजस्व प्रकरणों के निर्धारित समय-सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत की. इस पोर्टल के माध्यम से नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई समेत अन्य

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब

राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा के भीतर किया जाना है, लेकिन राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़

रहा है. आम नागरिकों की सुविधा व राजस्व प्रकरणों की सतत समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था किए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए थे.

राजस्व कार्यों का मुख्यमंत्री कार्यालय व राजस्व मंत्री कार्यालय समेत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी.

नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण के लिए भुइया सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग

पोर्टल की व्यवस्था की गई है. प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिए मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिव राजस्व विभाग, संचालक भू-अभिलेख, संभाग आयुक्त तथा जिला कलेक्टर के स्तर से सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी.

CM launches online monitoring portal to review resolution of revenue cases

■ Staff Reporter
RAIPUR, Mar 31

CHIEF Minister Bhupesh Baghel on Thursday launched an online monitoring portal to review the disposal of revenue cases within the stipulated time frame.

Through this portal, continuous monitoring of revenue works including name transfer, account division, demarcation, diversion and felling of tree can be done from the offices of Chief Minister, Revenue Minister and senior officials concerned. Revenue cases should be resolved within the time limit under the Public Service Guarantee Act.

However, the common citizens face a lot of troubles due to delay in disposal of revenue cases. Chief Minister Bhupesh

Baghel gave instructions to the Revenue Department to make arrangements for online monitoring of disposal of revenue cases keeping in view convenience of common citizens and for constant review of revenue cases.

An online monitoring portal has been added in 'Bhuiyan' software for redressal of unresolved cases of name transfer, account division, demarcation, diversion and tree felling, whose deadline has been crossed. In a bid to ensure timely disposal of cases, monitoring will be done directly from office of Chief Minister, Revenue Minister and Chief Secretary, Revenue Department Secretary, Director Land Records, Divisional Commissioner and District Collector's level through the monitoring portal.

■ Friday ■ April 1 ■ 2022

CITYLINE

3

Honorarium of Mayors, Corporators, Councilors doubled

- CM also transfers Rs 1124.92 crore to the bank accounts of farmers, livestock farmers, landless agricultural labourers, women groups and tendupatta collecting families
- CM inaugurated 4 new sub-divisions and 23 new tehsils in State and launched a web portal to review the redressal of revenue related complaints

■ Staff Reporter
RAIPUR, Mar 31

CHIEF Minister Bhupesh Baghel on Thursday made several announcements to strengthen the local self-government. To start with, Baghel announced to double the honorarium of Mayor, Corporators, Councilors, Speakers of municipal bodies, Corporators of nagar panchayats and their presidents and vice-presidents, fulfilling the demands of the MLAs who raised the issue in during the budget grant discussion in this budget session of the Assembly.

It may be recalled, Bilaspur MLA Shailesh Pandey had raised the issue when Chief Minister Baghel announced an increase in honorarium of sarpanch, panch, district panchayat, janpad panchayat presidents, mem-

bers etc in the Chhattisgarh Legislative Assembly. The Chief Minister also increased the development fund of Mayor, Corporators and Councilors by one and a half time.

For infrastructure development in urban bodies, development works worth Rs 5 crore will be sanctioned for all municipalities of State, Rs 3 crore for Nagar Panchayats, said the Chief Minister. Similarly, an amount of Rs 140 crore will be made available for development work in 14 municipal corporations of State. Thus a total amount of Rs 579 crore will be sanctioned, said the Chief Minister. This includes sanction of Rs 10 crore each to municipal corporations, Rs 5 crore each to municipalities and Rs 3 crore each to nagar panchayats for development works.

Announcement to double the financial power of the office bearers of all urban bodies was made to fulfill the concept of empowering local self-government, said the Chief Minister. The Chief Minister also tweeted it immediately after his announcements.

The Chief Minister said that unemployment rate in Chhattisgarh has shrunk to only 1.7 per cent, which is way less than the national average of 7.4 per cent.

Chief Minister transferred a total amount of Rs 1124.92 crore to the bank accounts of farmers, rural landless agricultural labourers, tendu patta collecting families, cattle rearing villagers,



Chief Minister Bhupesh Baghel, Speaker Dr. Charandas Mahant, Congress state in-charge P. L. Punia and Cabinet ministers during a programme at Chief Minister's official residence on Thursday.

women's groups directly.

On this occasion, he inaugurated 4 new sub-divisions and 23 new tehsils in State. CM also launched a web portal to review the redressal of revenue related complaints. For the expansion of Chief Minister's Urban Slum Health Scheme in the municipal councils and nagar panchayats of State, Baghel dedicated 60 new medical mobile units.

At the programme, Chief Minister transferred an amount of Rs 1029.31 crore to the accounts of 20 lakh 58 thousand farmers of State as the fourth instalment under Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana.

It is noteworthy that a total of Rs 11 thousand 180 crore 97 lakh has been paid under this scheme into the accounts of farmers in last two years. In order to provide financial support and justice to rural landless families, Chief Minister deposited an amount of Rs 71 crore 8 lakh in the bank accounts of 3 lakh 55 thousand landless families under Rajiv Gandhi Grameen

Bhumiless Krishi Mazdoor Nyay Yojana.

Chief Minister said that the payment of Rs 13.62 crore given to the cow dung vendors, Gauthan committees and women's groups under Godhan Nyay Yojana. Under this scheme, Rs 226.18 crore has been paid by State Government to the cattle rearers, self-help groups and Gauthan committees.

Under Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Collectors Social Security Scheme, an insurance amount of Rs 10 crore 91 lakh was paid to 728 Tendupatta collector families.

During the programme, Chief Minister released an amount of Rs 13.62 crore to cow dung vendors, Gauthan committees and women's groups under the Godhan Nyay Yojana. So far, a total of Rs 226.18 crore has been paid by State Government to the cattle rearers, self-help groups and Gauthan committees under this scheme. Under the Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangraha Samajik Suraksha

Mayor Dhebar thanks CM for hike in remuneration, local devpt fund

RAIPUR Municipal Corporation (RMC) Mayor Aijaz Dhebar extended gratitude towards Chief Minister Bhupesh Baghel for hiking remuneration and local development fund of public representatives at urban local bodies.

Mayor Dhebar offered full support to CM's call to strengthening the local self-administration. Mayor conveyed CM gratitude on part of the citizens. Mayor said Bhupesh Hai to Bharosa Hai slogan materialised.

Dhebar informed that he had requested CM Baghel for hiking the remuneration and Local Development Funds during the Vidhan Sabha session. CM Baghel realised the idea of progress in urban areas by fulfilling the demand.

Mayor informed that urban local bodies of Chhattisgarh have earned 66 awards in field of Swachhata in entire nation. Chhattisgarh has been the cleanest state in the nation for the past three years. The efforts to maintain the lead in all fields will continue and they'll try to earn first position in Swachhata ranking with all their might. Chief Minister Bhupesh Baghel sanctioned Rs 579 crore for infrastructural works in urban sprawls besides doubling the financial powers of ULB public representatives. CM also announced doubling the fund of Mayor, Speaker and Corporator.

Yojana, an insurance amount of Rs 10 crore 91 lakh was paid to 728 families engaged in collection of tendu leaves.

On this occasion, Chief Minister Bhupesh Baghel also expanded the scope of the Chief Minister's Urban Slum Health Scheme in State. After the municipal corporations, this scheme has now been implemented in municipalities and Nagar Panchayats as well.

In a bid to provide home access health facilities to the people, Baghel flagged off 60 new mobile medical units for urban bodies.

Speaker of Chhattisgarh Legislative Assembly Dr. Charandas Mahant presided over the programme. Former Member of Parliament and Chhattisgarh in-charge P. L. Punia and Cabinet ministers were present.

Dr. Mahant said that following the path shown by Father of the Nation Mahatma Gandhi, the Chhattisgarh Government has brought justice to every section of the society. Punia said that revolutionary schemes are being run by Chhattisgarh Government to provide direct financial help to the general public.